

फ़ाइल संख्या 370133/22/2020- टीपीएल

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टीपीएल डिवीजन)

दिनांक: 29 सितंबर, 2020

विषय-वस्तु: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ओ (4) और धारा 206 सी (1-1) के तहत दिशानिर्देश।

वित्त अधिनियम, 2020 ने आयकर अधिनियम 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) में एक नई धारा 194-ओ को जोड़ा है, जो यह अनिवार्य करती है कि 1 अक्टूबर, 2020 से, एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर वस्तुओं की बिक्री की सकल राशि या सेवा या दोनों के प्रावधान से एक प्रतिशत (अधिनियम की प्रस्तावित धारा 197 बी के प्रावधानों के अधीन) की दर से आयकर काटेगा, इसकी सुविधा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक या मंच के माध्यम से प्रदान की जाती है। हालांकि, कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार को निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने की स्थिति में उक्त कटौती से छूट प्रदान की गई है। यह कटौती ऐसी बिक्री या सेवा या दोनों की राशि को ई-कॉमर्स प्रतिभागी के खाते में जमा करते समय या ऐसे ई-कॉमर्स प्रतिभागी को भुगतान के समय, जो भी पहले हो, की जानी आवश्यक है।

2. वित्त अधिनियम, 2020 ने अधिनियम की धारा 206 सी में उप-धारा (1 एच) भी शामिल की, जो अनिवार्य करती है कि अक्टूबर, 2020 के पहले दिन से किसी भी विक्रेता को खरीदार से 0.1 प्रतिशत के बराबर कर एकत्र करने के लिए पिछले वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक मूल्य या कुल मूल्य के किसी भी सामान की बिक्री के लिए विचार के रूप में राशि प्राप्त करने के लिए विचार के रूप में राशि प्राप्त करना होगा (प्रस्तावित उप-धारा (10 ए) के प्रावधानों के अधीन) अधिनियम की धारा 206 सी) के तहत पचास लाख रुपये से अधिक की बिक्री आयकर के रूप में विचार की गई है। बिक्री विचार की राशि की प्राप्ति के समय संग्रह किया जाना अपेक्षित है।

3. अधिनियम की धारा 194-ओ की उप-धारा (4) और अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1-1) बोर्ड को (केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ) को सशक्त बनाता है ताकि कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किया जा सकें। कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड को विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अधिनियम की धारा 194-ओ की उप-धारा (4) और अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1-1) के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केंद्र सरकार की स्वीकृति से, निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है।

4. दिशा-निर्देश

4.1 विभिन्न समाशोधन केन्द्र के माध्यम से किए गए लेनदेन पर प्रयोज्यता:

4.1.1 यह दर्शाया गया है कि कुछ एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों के मामले में अधिनियम की धारा 194-ओ और धारा 206 सी की उपधारा (1 एच) में निहित स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के प्रावधानों को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। यह कहा गया है कि कभी-कभी इन लेनदेन में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच किसी से एक भी अनुबंध नहीं होता है।

4.1.2 ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 194 ओ और धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) के प्रावधान निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे:-

(i) प्रतिभूतियों और वस्तुओं में लेन-देन जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से कारोबार किया जाता है या मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम द्वारा स्वीकृत और निपटाया जाता है, जिसमें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम शामिल हैं;

1Page

(ii) बिजली में लेनदेन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र सीईआरसी के विनियमन 21 के अनुसार पंजीकृत पावर एक्सचेंजों के माध्यम से कारोबार किए गए; और

इस प्रयोजन के लिए, --

(i) 'मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम' का अर्थ अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ईई) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में सौंपा गया अर्थ होगा।

(ii) 'मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज' का अर्थ अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में सौंपा गया होगा; और

(iii) 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' का अर्थ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (क्यू) में दिया गया होगा।

4.2 भुगतान गेटवे पर प्रयोज्यता:

4.2.1 ई-कॉमर्स संव्यवहार में, भुगतान आम तौर पर भुगतान गेटवे द्वारा सुविधाजनक होते हैं। यह दर्शाया गया है कि इन संव्यवहारों में, धारा 194-ओ की प्रयोज्यता दो बार हो सकती है यानी एक बार ई-मेन कॉमर्स ऑपरेटर पर जो माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान या दोनों की सुविधा प्रदान कर रहा है और एक बार भुगतान गेटवे पर जो सेवा की सुविधा के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। एक खरीदार ई-कॉमर्स वेबसाइट 'XYZ' पर एक लाख रुपये के सामान खरीदता है। वह 'ABC' के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक लाख रुपये का भुगतान करता है। इन तथ्यों पर धारा 194-ओ के तहत कर में कटौती करने के लिए देयता 'XYZ' और 'ABC' दोनों पर गिर सकती है।

4.2.2 इस कठिनाई को दूर करने के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि भुगतान गेटवे को लेनदेन पर अधिनियम की धारा 194-ओ के तहत कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसी लेनदेन पर अधिनियम की धारा 194-ओ के तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर काटा गया है। इसलिए, उपरोक्त उदाहरण में, यदि 'XYZ' ने धारा 194 ओ के तहत एक लाख रुपये पर कर की कटौती की है, तो 'ABC' को उसी लेनदेन पर अधिनियम की धारा 194 ओ के तहत कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी। उचित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, 'ABC' कर की कटौती के बारे में 'XYZ' से एक उपक्रम ले सकता है।

•

4.3 बीमा एजेंट या बीमा समूहक पर प्रयोज्यता:

4.3 .1 यह दर्शाया गया है कि कई मामलों में बीमा एजेंटों या बीमा एग्रीगेटर्स(समूहक) बाद के वर्षों के लिए बीमा कंपनी और खरीदार के बीच लेन-देन में कोई भागीदारी नहीं है। यह दर्शाया गया है कि बाद के वर्षों में, कर में कटौती करने की देयता बीमा एजेंटों या बीमा एग्रीगेटरों पर उत्पन्न हो सकती है, भले ही लेनदेन सीधे बीमा कंपनी के साथ पूरा हो गया हो। इससे बीमा एजेंटों/एग्रीगेटर्स के लिए कठिनाई हो सकती है।

4.3.2 इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह प्रावधान किया जाता है कि पहले वर्ष के बाद के वर्षों में, यदि बीमा एजेंट या बीमा एग्रीगेटर की बीमा कंपनी और बीमा पॉलिसी के खरीदार के बीच लेनदेन में कोई भागीदारी नहीं है, तो वह उन बाद के वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 194-ओ के तहत कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, बीमा कंपनी को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत बाद के वर्षों के लिए बीमा एजेंट या बीमा एग्रीगेटर को किए गए कमीशन भुगतान, यदि कोई हो, पर कर काटने की आवश्यकता होगी।

4.4 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दहलीज़ की गणना.

4.4.1. चूंकि अधिनियम की धारा 194-ओ और धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) दोनों पहली अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होंगी, इसलिए यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया कि इन धाराओं के तहत निर्दिष्ट विभिन्न सीमाओं की गणना कैसे की जाएगी और क्या पहली अक्टूबर 2020 से पहले प्राप्त राशि के संबंध में कर को काटने / एकत्र करने की आवश्यकता है।

4.4.2 यह स्पष्ट किया गया है कि, -

(i) चूंकि एक व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार (ई-कॉमर्स प्रतिभागी होने के नाते जिसने अपना पैन/आधार प्रस्तुत किया है) के लिए पांच लाख रुपये की सीमा पिछले वर्ष के संबंध में है, इसलिए अधिनियम की धारा 194-ओ के तहत कटौती शुरू करने के लिए बिक्री या सेवाओं या दोनों की राशि की गणना 1 अप्रैल, 2020 से की जाएगी। इसलिए, यदि ऐसे व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार के संबंध में पिछले वर्ष 2020-21 (30 सितंबर 2020 तक की अवधि सहित) के दौरान बिक्री या सेवाओं या दोनों की सकल राशि पांच लाख रुपये से अधिक है, तो धारा 194-ओ का प्रावधान 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद जमा या भुगतान की गई किसी भी राशि पर लागू होगा।

(ii) चूंकि अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (आई एच) बिक्री विचार प्राप्त होने पर लागू होती है, इसलिए इस उप-धारा का प्रावधान 1 अक्टूबर 2020 से पहले प्राप्त किसी भी बिक्री विचार पर लागू नहीं होगा। नतीजतन, यह 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद प्राप्त सभी बिक्री विचार (बिक्री के लिए प्राप्त अग्रिम सहित) पर लागू होगा, भले ही बिक्री 1 अक्टूबर 2020 से पहले की गई हो।

(iii) चूंकि पचास लाख रुपये की सीमा पिछले वर्ष के संबंध में है, इसलिए धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) के अंतर्गत टीसीएस को सक्रिय करने के लिए बिक्री की प्राप्ति की गणना पहली अप्रैल, 2020 से की जाएगी। इसलिए, यदि विक्रेता होने वाले किसी व्यक्ति को खरीदार से 30 सितंबर 2020 तक पहले ही पचास लाख रुपये या उससे अधिक प्राप्त हो चुके हैं, तो धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) के तहत टीसीएस ऐसे खरीदार से पिछले वर्ष के दौरान या उसके बाद विक्रय प्रतिफल की सभी रसीदों पर लागू होगा।

4.5 मोटर वाहन की बिक्री के लिए प्रयोज्यता:

4.5. अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1 एफ) के प्रावधान दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के मोटर वाहन की बिक्री पर लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) उप-धारा (1 एफ) के तहत कवर की गई प्रयोज्य वस्तुओं को बाहर करती है। यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि क्या सभी मोटर वाहनों को अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) की प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है।

4.5.2 इस संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि उप-धाराओं (1 एच) और (1 एफ) का दायरा अलग-अलग उप-धारा (1 एफ) मोटर वाहन की एकल बिक्री पर आधारित है, उप-धारा (1 एच) पिछले वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक की प्राप्ति के लिए है। जबकि उप-धारा (1 एफ) केवल उपभोक्ता को बिक्री के लिए है और डीलरों के लिए नहीं है, उप-धारा (1 एच) दहलीज़ के ऊपर सभी बिक्री के लिए है। इसलिए, कठिनाई को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, -

(i) एक डीलर से विक्रय प्रतिफल की प्राप्ति अधिनियम के उप-धारा (1 एच) के तहत टीसीएस के अधीन होगी, यदि ऐसी बिक्री अधिनियम की धारा 206C की उप-धारा (1 एफ) के तहत टीसीएस के अधीन नहीं है।

(ii) उपभोक्ता को बिक्री के मामले में, खरीदार को दस लाख रुपये या उससे कम मूल्य के मोटर वाहन की बिक्री के लिए विक्रय प्रतिफल की प्राप्ति अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) के तहत टीसीएस के अधीन होगी, यदि पिछले वर्ष के दौरान ऐसे वाहनों के लिए विक्रय प्रतिफल की प्राप्ति पिछले वर्ष के दौरान पचास लाख रुपये से अधिक है।

3 Page

(iii) उपभोक्ता को बिक्री के मामले में, दस लाख रुपये से अधिक के मूल्य के मोटर वाहन की बिक्री के लिए विक्रय प्रतिफल प्राप्त करने के लिए टीसीएस की धारा 206C की उप-धारा (1 घंटे) के तहत टीसीएस के अधीन नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी बिक्री टीसीएस के अधीन है। अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1 एफ) के तहत,

4.6 विक्रय रिटर्न, छूट या अप्रत्यक्ष करों के लिए समायोजन

4.6.1 यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) के तहत कर के संग्रह के उद्देश्य से जीएसटी सहित विक्रय रिटर्न, छूट या अप्रत्यक्ष करों के लिए समायोजन करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1 एच) के तहत कर के संग्रह के लिए बिक्री रिटर्न या छूट या जीएसटी सहित अप्रत्यक्ष करों के कारण कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संग्रह बिक्री विचार की राशि की प्राप्ति के संदर्भ में किया जाता है।

4.7 प्रवासी एयरलाइनों को ईंधन की आपूर्ति

4.7.1 यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) के प्रावधान भारत में हवाई अड्डों पर अनिवासी एयरलाइनों को आपूर्ति किए गए ईंधन पर लागू होंगे। कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 206 सी की उप-धारा (1 एच) के प्रावधान भारत में हवाई अड्डों पर अनिवासी एयरलाइनों को आपूर्ति किए गए ईंधन के लिए प्राप्त विक्रय प्रतिफल पर लागू नहीं होंगे।

काँपी:

1. PS to FM/ OSD to FM/ PS to MOS(F)/ OSD to MoS(F)
2. PPS to Secretary (Revenue)
3. Chairman, CBDT & All Members, CBDT
4. All Pr. DGsIT/ Pr. CCsIT
5. All Joint Secretaries/ CsIT/ Directors/ Deputy Secretaries/ Under Secretaries of CBDT
6. The C&AG of India
7. The J S & Legal Adviser, Ministry of Law & Justice, New Delhi
8. CIT (M&TP), Official Spokesperson of CBDT
9. O/o Pr. DGIT (Systems) for uploading on official website
10. JCIT (Database Cell) for uploading on www.irsofficersonline.gov.in